**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1

उत्‍तर देने की तारीख: 24.11.2014

**सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत आदर्श**

**विद्यालयों की स्थापना किया जाना**

**\* डा॰ संजय सिंहः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के शैक्षिक रूप से अगड़े समस्त विकास खण्डों में सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत आदर्श विद्यालय खोले जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु कुछ संस्थाओं को चिह्नित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी संस्थाओं को आदर्श विद्यालय खोलने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की

गई है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत आदर्श विद्यालयों की स्थापना’ करने के संबंध में संसद सदस्‍य डॉ॰ संजय सिंह द्वारा दिनांक 24.11.2014 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख) : मॉडल स्‍कूल योजना में ब्‍लॉक स्‍तर पर उत्‍कृष्‍टता के बेंचमार्क के रूप में प्रति ब्‍लॉक एक स्‍कूल की दर से 6000 मॉडल स्‍कूलों को स्‍थापित करने पर विचार किया गया। इस योजना में कार्यान्‍वयन की दो पद्धतियां अर्थात् (i) राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकारों के माध्‍यम से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्‍लॉकों में 3500 स्‍कूल स्‍थापित करना और (ii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत शेष 2500 स्‍कूल उन ब्‍लॉकों में स्‍थापित करना जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं।

(ग) से (ड़) : सरकार ने मॉडल स्‍कूल योजना के सार्वजनिक-निजी-भागीदारी घटक की समीक्षा आरम्‍भ करने का निर्णय किया है। भावी कार्रवाई समीक्षा के नतीजे पर निर्भर करेगी।

\*\*\*\*\*